



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2013/ज्येष्ठ 6, 1935

No. 159]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2013/JYAISTHA 6, 1935

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 01)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2013

फा. सं. 1-19/2012-बीएंडसीएस.—भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii), (iii) (iv) व (v) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

- (क) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और
- (ख) दिनांक 09 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II धारा 3 की उप-धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 39 [सा.का.नि. 44(अ) तथा 45(अ)] के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

भाग—I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 01) कहा जाएगा।  
(2) यह आदेश, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. **"अनुप्रयोज्यता."**—यह आदेश, संपूर्ण भारत में उपभोक्ताओं को प्रदत्त डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही केबल टीवी सेवाओं पर लागू होगा।
3. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-  
(क) "अधिनियम" से आशय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) से है;

- (ख) “प्राधिकरण” से आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;
- (ग) “डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली” से आशय है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध साफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिन्हें एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से डिजिटल एड्रसेबल केबल प्रणाली के सिग्नल कूट (एनक्रिप्टिड) रूप में भेजे जा सकते हैं और जिनका ऐसे उपभोक्ता की सुस्पष्ट पसन्द और अनुरोध पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा कन्डीशनल एक्सेस प्रणाली और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, उपभोक्ता के परिसर में सक्रिय कन्डीशनल एक्सेस वाले किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद (डिकोड) किया जा सकता है;”
- (घ) “मल्टी सिस्टम ऑपरेटर” से आशय है कोई ऐसा केबल ऑपरेटर जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 सी के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो किसी प्रसारक या इसकी प्राधिकृत एजेंसियों से कोई कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और मल्टीपल उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही अथवा उसकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियाँ सम्मिलित हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए सहित एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से, साथ-साथ प्राप्त करने के लिए इन्हें या तो री-ट्रांसमिट करता है अथवा अपनी स्वयं की कार्यक्रम सेवा को ट्रांसमिट करता है ;
- (च) “सेट टॉप बाक्स” का आशय एक ऐसे उपकरण से है जो टेलीविजन से जुड़ा हुआ या उसका हिस्सा होता है; और जो एड्रसेबल प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता को अनएनक्रिप्टेड/डिस्क्रिम्बल्ड रूप में सब्सक्राइब किए गए चैनल प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और इसमें शामिल है:-
- (1) सेट टॉप बाक्स तथा सेट टॉप बाक्स के लिए रिमोट कंट्रोल; और
- परंतु इसमें टेलीविजन रिसीवर सेट, कम्प्यूटर अथवा ऐसा कोई अंत्य उपकरण शामिल नहीं है;
- (छ) “आदेश” से आशय है “दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 01) ;
- (ज) “सामान्य उपभोक्ता” से आशय है कोई उपभोक्ता, जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और उसका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है;
- (झ) “मानक टैरिफ पैकेज” से आशय, प्राधिकरण द्वारा डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली के सामान्य उपभोक्ता को कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए निर्धारित टैरिफ से है ;
- (ण) इन आदेशों में प्रयुक्त किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम, नियमों और इनके तहत बनाए गए विनियमों या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और नियमों एवं इनके तहत बनाए गए विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और कथनों का अर्थ वही माना जाएगा, जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है।

## भाग-II

### सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु टैरिफ

4. **सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु टैरिफ-**(1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित भारतीय मानदण्डों, यदि कोई हो तो, पर खरा-उतरने वाले सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु मानक टैरिफ पैकेज की पेशकश करेगा।
- (2) दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) के तहत उपलब्ध विकल्पों के अतिरिक्त, सामान्य उपभोक्ता को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर सेट टॉप बाक्स की खरीद करने का विकल्प होगा तथा सामान्य उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, उपभोक्ता द्वारा इंगित परिसर पर सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति तथा संस्थापन करेगा।

## भाग- III

### विविध

5. **रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं-**(1) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति तथा संस्थापना हेतु सभी टैरिफ पैकेजों तथा अन्य निबंधन व शर्तों के ब्योरों की 15 जून, 2013 तक प्राधिकरण को जानकारी देगा।
- (2) उप-खंड (1) के तहत संसूचित टैरिफ पैकेज में कोई परिवर्तन तथा सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति और संस्थापन के लिए आरंभ किए गए नए पैकेज की जानकारी ऐसे परिवर्तन या आरंभ किए जाने, जैसा भी मामला हो, के कम से कम सात दिन पूर्व प्राधिकरण को दी जाएगी।

सुधीर गुप्ता, सचिव (आई/सी)

[विज्ञापन III / 4 / असाधारण / 142 / 13]

**टिप्पणी :-** इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन “दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल) सेवाएं (पांचवां) (डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2013 (2013 का 01) के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

अनुसूची

**डिजिटल एंड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली के लिए सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति और संस्थापना**  
**हेतु मानक टैरिफ पैकेज**  
**( खंड-4 देखें )**  
**विकल्प-1**

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति सेट टॉप बाक्स का प्रतिमाह किराया	55.66 /- रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात्	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा सेट टॉप बाक्स, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा ।
3	प्रतिभूति जमा राशि (प्रतिदेय)	400 /- रुपए
4	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि से कटौती	कुछ नहीं
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

टिप्पणी :-

- सेट टॉप बाक्स की संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर, सामान्य उपभोक्ता को संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी ।
- उपभोक्ता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के अंदर किसी भी समय सेट टॉप बाक्स को वापस किए जाने पर, बिना कोई कटौती किए, संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि का प्रतिदाय किया जाएगा बशर्ते कि सेट टॉप बाक्स से छेड़छाड़ न की गई हो ।
- कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा, कोई संस्थापना प्रभार या पुनः संस्थापना प्रभार नहीं होंगे ।

**विकल्प-2**

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति सेट टॉप बाक्स का प्रतिमाह किराया	50.66 /- रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात्	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा सेट टॉप बाक्स, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा ।
3	प्रतिभूति जमा राशि (प्रतिदेय)	800 /- रुपए
4	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा राशि से कटौती	कुछ नहीं
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

**टिप्पणी :-**

1. सेट टॉप बाक्स की संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर, सामान्य उपभोक्ता को संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि बिना किसी कटौती के वापस की जाएगी ।
2. उपभोक्ता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के अंदर किसी भी समय सेट टॉप बाक्स को वापस किए जाने पर बिना कोई कटौती किए संपूर्ण प्रतिभूति जमा राशि का प्रतिदाय किया जाएगा बशर्ते कि सेट टॉप बाक्स से छेड़छाड़ न की गई हो ।
3. कनेक्शन को अन्यत्र ले जाने के अलावा, कोई संस्थापना प्रभार या पुनःसंस्थापना प्रभार नहीं होंगे ।

**विकल्प – 3**

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति सेट टॉप बाक्स का प्रतिमाह किराया	46.80 / – रुपए (कर के अतिरिक्त)
2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात्	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/ब्यूईंग कार्ड के अलावा सेट टॉप बाक्स, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा ।
3	प्रतिभूति जमा राशि (समायोज्य)	400 / – रुपए
4	सेट टॉप बाक्स की वापसी पर प्रतिदाय प्रतिभूति जमाराशि	संलग्न तालिका-क के अनुसार
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	संक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/ब्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

**टिप्पणी :-**

1. यदि सामान्य उपभोक्ता सेट टॉप बाक्स को संस्थापित किए जाने की तिथि के 03 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय सेट टॉप बाक्स वापस करता है तो, प्रतिभूति जमा राशि तालिका-क में विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार वापस लौटाई जाएगी बशर्ते कि सेट-टॉप बाक्स के साथ छेड़छाड़ न की गई हो ।
2. यदि महीने के अंतिम दिन से पहले सेवा काटी जाती है तो, उक्त महीने के अंत में वापस करने के लिए दर्शाई गई प्रतिभूति राशि, सेट टॉप बाक्स के लौटाने पर वापस कर दी जाएगी ।
3. कनेक्शन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के मामले के अलावा, कोई संस्थापन अथवा पुनःसंस्थापन प्रभार नहीं लिए जाएंगे ।

**तालिका-क (विकल्प-3)****आंकड़े – रुपए में**

वर्ष	माह के अंत में	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा
प्रथम वर्ष	पहला	391.13
	दूसरा	382.16
	तीसरा	373.07
	चौथा	363.86
	पांचवां	354.55
	छठा	345.11
	सातवां	335.56
	आठवां	325.89

	नौवां	316.10
	दसवां	306.18
	ग्यारहवां	296.14
	बारहवां	285.98
द्वितीय वर्ष	तेरहवां	275.69
	चौदहवां	265.27
	पन्द्रहवां	254.72
	सोलहवां	244.03
	सत्रहवां	233.22
	अठारहवां	222.27
	उन्नीसवां	211.18
	बीसवां	199.95
	इक्कीसवां	188.59
	बाइसवां	177.08
	तेइसवां	165.43
	चौबीसवां	153.63
तृतीय वर्ष	पच्चीसवां	141.68
	छब्बीसवां	129.59
	सत्ताईसवां	117.34
	अट्ठाईसवां	104.94
	उन्नतीसवां	92.39
	तीसवां	79.67
	इकतीसवां	66.80
	बत्तीसवां	53.77
	तैंतीसवां	40.58
	चौँतीसवां	27.22
	पैंतीसवां	13.69
	छत्तीसवां	0.00

## विकल्प-4

क्रम संख्या	विवरण	टैरिफ
1	पहले तीन वर्षों के लिए प्रति सेट टॉप बाक्स का प्रतिमाह किराया	32.93/-रुपए (कर के अतिरिक्त)

2	संस्थापना की तिथि से तीन वर्ष पश्चात्	कोई किराया नहीं । स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड के अलावा सेट टॉप बाक्स, उपभोक्ता की संपत्ति बन जाएगा।
3	प्रतिभूति जमा राशि (समायोज्य)	800/-रुपए
4	सेट टॉप बाक्स की वापसी पर प्रतिदाय प्रतिभूति जमा राशि	संलग्न तालिका-ख के अनुसार
5	संस्थापना प्रभार	कुछ नहीं
6	सक्रियण प्रभार	कुछ नहीं
7	स्मार्ट कार्ड/व्यूईंग कार्ड प्रभार	कुछ नहीं
8	संस्थापना की तिथि से तीन वर्षों के लिए मरम्मत तथा अनुरक्षण प्रभार	कुछ नहीं

**टिप्पणी :-**

- यदि सामान्य उपभोक्ता सेट टॉप बाक्स को संस्थापित किए जाने की तिथि के 03 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय सेट टॉप बाक्स वापस करता है तो, प्रतिभूति जमा राशि तालिका-ख में विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार वापस लौटाई जाएगी बशर्ते कि सेट-टॉप बाक्स के साथ छेड़छाड़ न की गई हो ।
- यदि महीने के अंतिम दिन से पहले सेवा काटी जाती है तो, उक्त महीने के अंत में वापस करने के लिए दर्शाई गई प्रतिभूति राशि, सेट टॉप बाक्स के लौटाने पर वापस कर दी जाएगी ।
- कनेक्शन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के मामले के अलावा, कोई संस्थापन अथवा पुनःसंस्थापन प्रभार नहीं लिए जाएंगे ।

**तालिका – ख (विकल्प-4)****आंकड़े-रुपए में**

वर्ष	माह के अंत में	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा
प्रथम वर्ष	पहला	782.27
	दूसरा	764.31
	तीसरा	746.14
	चौथा	727.73
	पांचवां	709.09
	छठा	690.23
	सातवां	671.12
	आठवां	651.78
	नौवां	632.19
	दसवां	612.36
	ग्यारहवां	592.29
द्वितीय वर्ष	बारहवां	571.96
	तेरहवां	551.37
	चौदहवां	530.53
	पन्द्रहवां	509.43
	सोलहवां	488.07

	सत्रहवां	466.44
	अठारहवां	444.54
	उन्नीसवां	422.36
	बीसवां	399.91
	इक्कीसवां	377.17
	बाइसवां	354.16
	तेइसवां	330.85
	चौबीसवां	307.25
तृतीय वर्ष	पच्चीसवां	283.36
	छब्बीसवां	259.17
	सत्ताईसवां	234.68
	अट्ठाइसवां	209.88
	उन्नतीसवां	184.77
	तीसवां	159.35
	इकतीसवां	133.61
	बत्तीसवां	107.55
	तैंतीसवां	81.16
	चौंतीसवां	54.44
	पैंतीसवां	27.39
	छत्तीसवां	0.00

## अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

- वर्तमान में भारत में केबल टीवी क्षेत्र का स्वरूप मुख्यतः एनालॉग है। एनालॉग केबल टीवी प्रणाली की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें क्षमता बाध्यताएं तथा नेटवर्क के गैर-एड्रसेबल स्वरूप प्रमुख हैं, के चलते केबल टेलीविजन क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव ने केबल टीवी क्षेत्र में एड्रसेबिलिटी के साथ डिजिटलाइजेशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तदनुसार, इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करने तथा लोक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से भादूविप्रा ने 05 अगस्त, 2010 को, देशभर में डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएस) के कार्यान्वयन तथा इसको प्राप्त करने की रूपरेखा सहित, सरकार को सिफारिश प्रस्तुत की। सरकार ने भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने संबंधी एक अध्यादेश को प्रख्यापित कर देश में डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली को लागू कर दिया। तत्पश्चात्, सरकार ने 11 नवम्बर, 2011 को एक अधिसूचना तथा 21 जून, 2012 को इसका संशोधन भी जारी किया, जिसमें देशभर में चार चरणों में डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें से प्रथम चरण को 31 अक्टूबर, 2012 तथा अंतिम चरण को 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना है। इससे संपूर्ण देश में एनालॉग केबल टीवी प्रणाली का समापन हो जाएगा। 25 दिसम्बर, 2011 का अध्यादेश बाद में 30 सितम्बर, 2011 को एक अधिनियम बन गया।
- डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली में चूंकि परिसर में प्राप्त सिग्नल डिजिटल तथा एनक्रिप्टिड रूप में होते हैं, अतः उपभोक्ता को टीवी कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अपने टीवी के साथ एक सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) जोड़ने की जरूरत होती है। अनेक प्रौद्योगिकियां साथ-साथ मौजूद होती हैं, संभव है कि एक ऑपरेटर द्वारा लगाया गया एसटीबी दूसरे ऑपरेटर द्वारा उपयोग किए जा रहे नेटवर्क के साथ व्यावहारिक रूप से काम न करे। अतः उपभोक्ता के चाहने पर, नए एसटीबी में पुनर्निवेश किए बिना, एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के पास स्थानांतरण पर सुगमता से जाना बाधित हो सकता है।

3. उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) के क्रियाकलाप का एक और केन्द्र है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने, वहन कर सकने योग्य दरों पर प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं की उपलब्धता को सुकर बनाने तथा यह भी सुनिश्चित करने कि प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवा विहित मानदण्डों के अनुरूप है, के लिए अनेक उपाय किए हैं।
4. उपभोक्ताओं को आसान निर्गमन विकल्प उपलब्ध कराने, वाजिब दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर एसटीबी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही साथ सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए, किराया आधार पर एसटीबी की पेशकश करने हेतु मानक टैरिफ पैकेज निर्धारित करते हुए एक मसौदा टैरिफ आदेश हितधारकों के साथ परामर्श करने हेतु प्रस्तुत किया गया। हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मसौदा टैरिफ आदेश को 11 अप्रैल, 2013 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस परामर्श प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में उपभोक्ताओं सहित हितधारकों से कुल 13 टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

### **हितधारकों की टिप्पणियां**

5. एमएसओ तथा एचआईटीएस ऑपरेटरों का यह मत है कि वितरकों/एमएसओ द्वारा हार्डवेयर की व्यवस्था करने की मौजूदा पद्धति भली-भांति कार्य कर रही है और इस संबंध में कोई टैरिफ आदेश लाए जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि बाजार के विकास तथा संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप एसटीबी के मूल्यों में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है। चूंकि एसटीबी सेवाओं की बजाए, वस्तुओं की श्रेणी में आता है, अतः डीटीएच ऑपरेटरों ने एसटीबी का टैरिफ निर्धारित करने हेतु भादूविप्रा के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाए हैं।
6. एसटीबी की लागत के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि एमपीईजी4 मॉडल के लिए एसटीबी की लागत 3000/-₹0 तक हो सकती है। साथ ही, संस्थापना, सक्रियण करने, अनुरक्षण आदि अन्य लागतों को जोड़ने पर यह 4000/-₹0 तक हो सकती है।
7. एसटीबी के जीवनकाल के मुद्दे पर यह कहा गया है कि एसटीबी या तत्संबंधी पुर्जों का निर्माण करने वाले विनिर्माता केवल 12 से 18 माह की वारंटी देते हैं, इसलिए ऑपरेटरों को उस अवधि के बाद मरम्मत प्रभार लेने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। एक अन्य टिप्पणी यह है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार 5000/-₹0 से कम मूल्य की परिसंपत्तियों का एक वर्ष में शत-प्रतिशत मूल्यह्रास होता और इसलिए किसी एसटीबी का जीवनकाल 01 वर्ष से अधिक नहीं माना जाना चाहिए।
8. धरोहर राशि के संबंध में एमएसओ की आशंकाएं निम्नलिखित हैं:- (1) 400/800/-₹0 की धरोहर राशि काफी कम है, (2) सेवा त्यागने पर उपभोक्ता एसटीबी को वापस नहीं करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बीमा कंपनियां ऐसे उत्पादों तथा सेवाओं की बीमा व्यवस्था करने को इच्छुक नहीं हैं। यह सुझाव दिया गया कि धरोहर राशि कम से कम 1500/-₹0 होनी चाहिए और किराए के अलावा 2.5 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास की कटौती कर धरोहर राशि की प्रतिपूर्ति की जाए।
9. उपभोक्ताओं ने मसौदा टैरिफ आदेश के उपबंधों का समर्थन किया तथा यह उल्लेख किया है कि एमएसओ द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही पद्धतियां उपभोक्ताओं के लिए क्षतिकारक हैं। सभी अनुरक्षण/प्रतिस्थापना/उन्नयन को सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता पर कोई प्रभार डाले बिना प्रदान करना चाहिए। साथ ही, यह पोर्टेबिलिटी संबंधी मुद्दों का भी समाधान कर देगा चूंकि उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता को बदलने करने की लागत के बारे में पता होगा।

### **टिप्पणियों का विश्लेषण**

#### **क्षेत्राधिकार**

10. डीटीएच एवं डीएस के साथ ही सभी एड्रसेबल प्रणालियों पर लागू टैरिफ आदेश में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि एड्रसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता परिसर उपकरण/एसटीबी को सीधे क्रय करने या किराया खरीद अथवा किराया आधार पर लेने की योजना, यदि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में चलाई गई हो, का विकल्प देना अपेक्षित होगा। तथापि, विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा उपयोग की जा रही अलग-अलग प्रौद्योगिकियों के कारण, किसी एक विशिष्ट ऑपरेटर की सेवाएं प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ता को उस ऑपरेटर से सामान्यतः एसटीबी प्राप्त करना होता है, और इसलिए एसटीबी, ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का एक अभिन्न अंग होता है। प्राधिकरण का यह दृष्टिकोण है कि एसटीबी के लिए विहित मानक टैरिफ पैकेज, टैरिफ प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए विनियम में पहले ही किए गए उपबंधों तथा टैरिफ आदेशों के अनुसरण में प्राधिकरण ने एसटीबी के लिए यह मानक टैरिफ पैकेज विहित किया है, जिसे सभी एमएसओ द्वारा उनके उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पेश करना होगा।

#### **मानक टैरिफ पैकेज विहित करने की आवश्यकता**

11. एड्रसेबल प्रणाली का उपयोग करते हुए सेवा प्रदाता द्वारा पेश की जा रही, प्रसारण तथा केबल टीवी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास अनिवार्य रूप से एसटीबी होना अपेक्षित है। तथापि, विभिन्न सेवा प्रदाता अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं और परिणामस्वरूप एक ऑपरेटर द्वारा लगाया गया एसटीबी दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क के साथ व्यावहारिक रूप से संयोज्य नहीं हो सकता है, जिससे अगर उपभोक्ता एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के पास जाना चाहे तो नए एसटीबी में पुनर्निवेश किए बिना आसानी से जाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
12. प्राधिकरण का यह मत है कि इस संबंध में उपभोक्ताओं के हितों को एसटीबी के वाणिज्यिक अंतःप्रचालन के उपबंध के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। अगर उपभोक्ता ऑपरेटर/प्लेटफार्म को किसी कारणवश बदलना चाहे तो, वाणिज्यिक अंतःप्रचालनता उसे निर्गमन का एक विकल्प प्रदान करती है। तदनुसार, भादूविप्रा के संगत विनियमों/टैरिफ आदेशों में यह अनिवार्य किया गया था कि डिजिटल एड्रसेबल प्रणालियों के ऑपरेटर प्रत्येक उपभोक्ता को एकमुश्त खरीद आधार अथवा किराया खरीद आधार अथवा किराया आधार अथवा प्राधिकरण द्वारा विहित योजना, यदि कोई हो तो, के आधार पर प्राप्त करने का विकल्प दें।
13. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डीटीएच सेवाओं के मामले में डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा परिसर उपकरण (उपभोक्ता परिसर उपकरण) हेतु उपभोक्ताओं को पेश की जा रही योजनाओं में काफी भिन्नता है तथा कभी-कभार ये ऐसी होती हैं कि उपभोक्ताओं के पास कोई व्यावहारिक निर्गमन



विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। विकल्प के रूप में इसके उपभोक्ताओं को किसी एक विशिष्ट ऑपरेटर या प्लेटफार्म से स्थानांतरण के मामले में पुनर्निवेश करना होता है।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, उपभोक्ताओं को सुगम निर्गमन का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, कम लागत तथा औचित्यपूर्ण निबंधन एवं शर्तों पर एसटीबी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा साथ ही साथ सेवा प्रदाता के हितों की संरक्षा करने के लिए एसटीबी की किराया आधार पर पेशकश करने हेतु यह मानक टैरिफ पैकेज विहित किया जा रहा है।
15. प्राधिकरण द्वारा विहित मानक टैरिफ पैकेज के अतिरिक्त, ऑपरेटर अपनी व्यापारिक योजना के अनुरूप तथा मौजूदा विनियम/टैरिफ आदेश के अंदर अपने उपभोक्ताओं को एसटीबी की आपूर्ति करने हेतु अपनी योजना की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपभोक्ताओं के पास प्राधिकरण द्वारा विहित मानक टैरिफ पैकेज तथा ऑपरेटरों द्वारा पेश की जा रही वैकल्पिक योजना में से चयन करने का विकल्प होगा। विहित मानक टैरिफ पैकेज उपभोक्ता को स्पष्ट, समझने में आसान निबंधन व शर्तों के साथ एसटीबी को खरीदने में समर्थ बनाता है और साथ ही उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरता है। इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि मानक टैरिफ पैकेज विहित करने से संपूर्ण क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा तथा प्रभावी वाणिज्यिक अंत:ऑपरेटरता को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराएगा।
16. प्राधिकरण ने यह पाया है कि ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के एसटीबी की पेशकश कर रहे हैं, जिनकी मूलभूत कार्यकरण के अतिरिक्त अलग-अलग विशेषताएं/क्षमताएं हैं जैसे "रिकॉर्डिंग सुविधा", "इंटरनेट/ब्रॉडबैंड संयोज्यता", "हाई डेफिनिशन/3-डी-रिसेप्शन" सुविधा आदि हैं। चूंकि ऐसे एसटीबी के लिए विशेषताओं तथा लागत के संदर्भ में काफी अंतर होगा और इसलिए केवल मूलभूत/आधारभूत एसटीबी के लिए ही मानक टैरिफ पैकेज उपलब्ध कराया गया है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित संगत भारतीय मानक के अनुरूप मानक डेफिनिशन टीवी सिग्नल (एसडीटीवी) की प्राप्ति के लिए बनाया गया है।
17. प्राधिकरण का मत है कि मानक टैरिफ पैकेज को विहित किए जाने से ऑपरेटरों के मध्य उपभोक्ताओं को वहनीय दर पर बेहतर टेलीविजन देखने का अनुभव उपलब्ध कराने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा ताकि मौजूदा उपभोक्ताओं को बनाए रखा जा सके और साथ ही नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जा सके। ऐसी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं सहित इस क्षेत्र के सभी हितधारकों को लाभ पहुंचेगा।

#### **मानक टैरिफ पैकेज विहित करने के लिए ध्यान में रखी गई एसटीबी की लागत**

18. परामर्श-पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों में, एसटीबी की लागत के संबंध में 3000/- से 4000/-रु० का सुझाव दिया गया, जिसमें संस्थापना तथा सक्रियण प्रभार शामिल है। मसौदा टैरिफ आदेश को तैयार करने से पहले, भादूविप्रा से प्राप्त प्रश्न के उत्तर में तीन प्रमुख एमएसओ ने एसटीबी की लागत को 1635 से 1939 रु० के बीच बताया। इस लागत में एसटीबी, सीएस, स्मार्ट-कार्ड, मिडलवेयर तथा सीमा-शुल्क एवं रॉयल्टी हेतु प्रभार, यातायात, मालभाड़ा तथा बीमा लागत शामिल है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक मर्चों की लागत तथा विशिष्ट रूप से एसटीबी की लागत में समय के साथ गिरावट हो रही है। उपरोक्त के आलोक में मानक टैरिफ पैकेज तैयार करने के लिए एसटीबी की लागत 1750 मानी गई है।
19. हितधारकों ने अपनी टिप्पणियों में बताया है कि एसटीबी या उसके पुर्जों के विनिर्माता केवल 12 से 18 माह तक वारंटी देते हैं। प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि समय के साथ प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुदृढ़ता में काफी सुधार हुआ है। तथापि, साथ ही साथ प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है तथा इलेक्ट्रॉनिक मर्चों के निष्पादन तथा विशेषताओं के संदर्भ में सुधार हुआ है और पुराने उत्पादन प्रयोग से हटते जाते हैं। यही बात एसटीबी के मामले में भी सटीक बैठती है। इसलिए, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए एसटीबी के जीवनकाल को 03 वर्ष माना गया है।

#### **एसटीबी की वापसी**

20. एक एड्रसेबल प्रणाली में, एसटीबी को उपभोक्ता द्वारा केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है यदि इसे, उसके सेवा प्रदाता द्वारा उसके नेटवर्क में उपयोग हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उपभोक्ता उस एसटीबी को अपने कब्जे में रख लेगा, जिसकी उसके लिए कोई उपयोगिता न हो। विशेष रूप से, जब यह दूसरे ऑपरेटर/प्लेटफार्म में स्थानांतरण पर जाने अथवा उस ऑपरेटर की सेवाओं से हटने की स्थिति में, जब यह धरोहर राशि को वापस करने से जुड़ा मामला हो। इसके आलोक में, एसटीबी के वापस न किए जाने के संबंध में ऑपरेटरों की आशकाएं मान्य नहीं हैं।

#### **मानक टैरिफ पैकेज को तैयार करने हेतु उपयोग किए गए मानदण्ड**

21. मानक टैरिफ पैकेज को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है :-

- (1) एसटीबी की कुल लागत 1750/-रुपए मानी गई है।
- (2) एसटीबी के जीवनकाल को 03 वर्ष माना गया है।
- (3) अवशिष्ट मूल्य को शून्य माना गया है।
- (4) प्रतिमाह किराया, 36 माह की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर (1.25 प्रति माह की दर पर) समान मासिक किस्त (ईएमआई) के आधार पर एसटीबी की लागत पर आधारित है।
- (5) उन विकल्पों में जहां धरोहर जमा राशि का प्रतिदाय किया जाना है, धरोहर जमा राशि पर ब्याज को किराए में समायोजित कर लिया गया है।
- (6) उन विकल्पों में जहां धरोहर जमा राशि को समायोजित करना हो, वहां शेष धरोहर जमा राशि पर प्रतिमाह ब्याज को किराए में समायोजित कर लिया गया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (FIFTH) (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TV SYSTEMS) TARIFF ORDER, 2013****(No. 1 of 2013)****NOTIFICATION**New Delhi, the 27<sup>th</sup> May, 2013

**No. 1-19/2012- B&CS.**—In exercise of powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,—

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of Section 2 and clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the said Act, and
- (b) published under notification No. 39 [S.O. 44 (E) and 45 (E)] dated the 9<sup>th</sup> January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),—

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order, namely:—

**PART-I****PRELIMINARY**

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fifth) (Digital Addressable Cable TV Systems) Tariff Order, 2013 (No. 1 of 2013).

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Applicability.**—This order shall be applicable to cable TV services provided to the subscribers through digital addressable systems, throughout the territory of India.

**3. Definitions.**—In this order, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (b) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub section (1) of Section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (c) “digital addressable systems” means an electronic device (which includes hardware and its associated software) or more than one electronic device put in an integrated system through which signals of digital addressable system can be sent in encrypted form, which can be decoded by the device or devices, having an activated Conditional Access System at the premises of the subscriber within the limits of authorisation made, through the Conditional Access System and the subscriber management system, on the explicit choice and request of such subscriber, by multi-system operator;
- (d) “multi-system operator” means a cable operator who has been granted registration under rule 11C of the Cable Television Networks Rules, 1994 and who receives a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called;
- (e) “set top box” means a device, which is connected to, or is part of a television and which allows a subscriber to receive in unencrypted and descrambled form subscribed channels through an addressable system and includes-----
  - (i) the set top box and the remote control for set top box; and but shall not include a television receiver set, computer or any such end equipment ;
- (f) “order” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fifth) (Digital Addressable Cable TV Systems) Tariff Order, 2013 (No. 1 of 2013);
- (g) “ordinary subscriber” means any subscriber who receives a programming service from a service provider and uses the same for his domestic purposes;
- (h) “standard tariff package” means a tariff determined by the Authority for supply and installation of a set top box to the ordinary subscriber of cable TV services provided through digital addressable systems for receiving programmes;

(i) all other words and expression used in this order but not defined, and defined in the act and rules and regulations made thereunder or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and the rules and regulations made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

## PART-II

### TARIFF FOR SUPPLY AND INSTALLATION

#### OF SET TOP BOXES

**4. Tariff for supply and installation of set top boxes.**—(1) Every multi system operator shall, without prejudice to the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (No.1 of 2010), offer to every ordinary subscriber the standard tariff package, for supply and installation of the set top box, conforming to the Indian Standard, if any, set by the Bureau of Indian Standard, specified in the Schedule.

(2) In addition to the option available under the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (No.1 of 2010), the ordinary subscriber shall have option to acquire the set top box at the rate and the terms and conditions specified in the Schedule and the multi system operator shall, on receipt of request from the ordinary subscriber, supply and install the set top box at the premises indicated by the subscriber.

## PART-III

### MISCELLANEOUS

**5. Reporting Requirement.**—(1) Every multi system operator shall report to the Authority by the 15<sup>th</sup> of June, 2013, the details of all tariff packages and other terms and conditions for supply and installation of the set top box.

(2) Any change in the tariff package reported under sub-clause (1) and the introduction of a new tariff package for supply and installation of set top box shall be reported to the Authority at least seven days prior to such change or introduction, as the case may be.

SUDHIR GUPTA, Secy.(I/C)

[ADVT-III/4/Exty./142/13]

**Note :—**The Explanatory Memorandum annexed to this order explains the objects and reasons of “The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fifth) (Digital Addressable Cable TV Systems) Tariff Order, 2013 (No. 1 of 2013)”.

## SCHEDULE

### Standard Tariff Package for supply and installation of set top box for cable TV services provided through digital addressable systems

(see clause 4)

#### OPTION – I

Sl.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per set top box for the first three years	Rs. 55.66 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The set top box shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Refundable)	Rs. 400/-

4.	Deduction from Refundable Security Deposit	Nil
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation Charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

**Note :-**

1. After the expiry of three years from the date of installation of set top box, the entire security deposit shall be refunded to the ordinary subscriber without any deductions.
2. The full security deposit without any deduction shall be refunded to the subscriber, if he returns the set top box, at any point of time, within a period of three years, provided that the set top box has not been tampered with.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

**OPTION – II**

Sl.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per set top box for the first three years	Rs.50.66 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The set top box shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Refundable)	Rs. 800
4.	Deduction from Refundable Security Deposit	Nil
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation Charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

**Note :-**

1. After the expiry of three years from the date of installation of set top box, the entire security deposit shall be refunded to the ordinary subscriber without any deductions.
2. The full security deposit without any deduction shall be refunded to the subscriber if he returns the set top box, at any point of time, within a period of three years, provided that the set top box has not been tampered with.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

**OPTION – III**

Sl.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per set top box for the first three years	Rs.46.80 (exclusive of taxes)

2.	After three years from the date of installation	No rent. The set top box shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Adjustable)	Rs. 400
4.	Amount of Security Deposit refunded on return of the Set Top Box	As per attached Table-A
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation Charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

**Note: -**

1. If the ordinary subscriber returns the set top box, any time before the completion of three years from the date of installation of set top box, the Security Deposit shall be refunded as per the amount specified in the Table-A, provided that the set top box has not been tampered with.
2. In case of disconnection of service before the last day of the month, balance security deposit shown as refundable at the end of that month, in Table-A shall be refunded on return of set top box.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

**Table-A (OPTION-III)***Figure in Rs.*

Year	End of Month	Security deposit refundable
First year	First	391.13
	Second	382.16
	Third	373.07
	Fourth	363.86
	Fifth	354.55
	Sixth	345.11
	Seventh	335.56
	Eighth	325.89
	Ninth	316.10
	Tenth	306.18
	Eleventh	296.14
	Twelfth	285.98
Second year	Thirteenth	275.69
	Fourteenth	265.27
	Fifteenth	254.72
	Sixteenth	244.03

	Seventeenth	233.22
	Eighteenth	222.27
	Nineteenth	211.18
	Twentieth	199.95
	Twenty first	188.59
	Twenty second	177.08
	Twenty third	165.43
	Twenty fourth	153.63
Third year	Twenty fifth	141.68
	Twenty sixth	129.59
	Twenty seventh	117.34
	Twenty eighth	104.94
	Twenty ninth	92.39
	Thirtieth	79.67
	Thirty first	66.80
	Thirty second	53.77
	Thirty third	40.58
	Thirty fourth	27.22
	Thirty fifth	13.69
	Thirty sixth	0.00

**OPTION – IV**

Sl.	Particulars	Tariff
1	Rent per month per set top box for the first three years	Rs.32.93 (exclusive of taxes)
2.	After three years from the date of installation	No rent. The set top box shall become the property of the subscriber except smart card/viewing card
3.	Security Deposit (Adjustable)	Rs. 800
4.	Amount of Security Deposit refunded on return of the Set Top Box	As per attached Table-B
5.	Installation Charges	Nil
6.	Activation Charges	Nil
7.	Smart Card/Viewing Card Charges	Nil
8.	Repair and Maintenance Charges for three years from the date of installation	Nil

**Note: -**

1. If the ordinary subscriber returns the set top box, any time before the completion of three years from the date of installation of set top box, the Security Deposit shall be refunded as per the amount specified in the Table-B, provided that the set top box has not been tampered with.
2. In case of disconnection of service before the last day of the month, balance security deposit shown as refundable at the end of that month, in Table-B shall be refunded on return of set top box.
3. There shall be no installation charges or re-installation charges except in case of shifting of connection.

**Table-B (OPTION-IV)***Figure in Rs.*

Year	End of the Month	Security deposit refundable
First year	First	782.27
	Second	764.31
	Third	746.14
	Fourth	727.73
	Fifth	709.09
	Sixth	690.23
	Seventh	671.12
	Eighth	651.78
	Ninth	632.19
	Tenth	612.36

	Eleventh	592.29
	Twelfth	571.96
Second year	Thirteenth	551.37
	Fourteenth	530.53
	Fifteenth	509.43
	Sixteenth	488.07
	Seventeenth	466.44
	Eighteenth	444.54
	Nineteenth	422.36
	Twentieth	399.91
	Twenty first	377.17
	Twenty second	354.16
	Twenty third	330.85
	Twenty fourth	307.25
Third year	Twenty fifth	283.36
	Twenty sixth	259.17
	Twenty seventh	234.68
	Twenty eighth	209.88
	Twenty ninth	184.77
	Thirtieth	159.35
	Thirty first	133.61
	Thirty second	107.55
	Thirty third	81.16
	Thirty fourth	54.44
	Thirty fifth	27.39
	Thirty sixth	0.00

**Annexure****Explanatory Memorandum**

1. The cable TV sector in India, at present, is primarily analog in nature. The inherent limitation of the analog cable TV systems has posed several challenges in the cable TV sector, mainly due to capacity constraints and non-addressable nature of the network. The evolution of technology paved way for bringing about digitization with addressability in the cable TV sector. Accordingly, after studying the subject at length and undertaking a public consultation process, TRAI, on 5<sup>th</sup> August 2010, gave its recommendations to the Government of India for implementation of Digital Addressable Cable TV Systems (DAS) across the country along with a roadmap to achieve the same. The Government has accepted the recommendations of TRAI and on 25<sup>th</sup> October, 2011, promulgated an Ordinance amending the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, enabling the implementation of Digital Addressable Cable TV Systems in India. Thereafter, the Government also issued a notification dated 11<sup>th</sup> November, 2011 and its amendment dated 21<sup>st</sup> June 2012, which laid down the roadmap for implementation of Digital Addressable Cable TV Systems in the country in a phased manner in four phases, with the first phase scheduled for 31<sup>st</sup> Oct. 2012 and the final phase to be completed by 31<sup>st</sup> December 2014.



This will lead to sunset of Analogue Cable TV Systems in the entire country. The Ordinance dated 25<sup>th</sup> October, 2011, subsequently, on 30<sup>th</sup> December, 2011, became an Act.

2. In Digital Addressable Cable TV Systems, a subscriber needs a set-top-box (STB) to be connected with his TV set for reception of TV programmes as the signal received at his premises is in digital and encrypted form. Since variegated technologies co-exist, the STBs deployed by one operator may not be practically compatible with the network of another operator, hampering easy migration of the subscriber from one operator to another, in case the subscriber wishes to do so, without re-investing in a new STB.
3. Consumer protection is one of the focus areas of Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). The Authority has taken several measures to protect the interest of the consumers, facilitate availability of broadcasting and cable television services at affordable price and to ensure that Quality of Service being provided to the consumer in the broadcasting and cable television sector is in accordance with the prescribed norms.
4. To provide an easy exit option to the subscribers, ensure availability of STBs at reasonable price and terms and conditions and, at the same time, to protect the interest of the service providers, a draft tariff order prescribing standard tariff package for offering of STBs on rental basis was put up for consultation with the stakeholders. The draft tariff order was uploaded on TRAI website on 11<sup>th</sup> April 2013, inviting the comments from the stakeholders. In response to this consultation process, a total of 13 comments were received from the stakeholders, including consumers.

#### **Comments of Stakeholders**

5. MSOs and HITS operator are of the opinion that the current practice of provisioning of hardware by distributors/MSOs is working well and there is no need to bring in any tariff order in this regard. It has been further stated that the prices of STBs are showing downward trend with growth in market and rise in volumes. DTH operators have questioned the jurisdiction of TRAI to fix the tariff of STBs as STBs come under the category of goods and not services.
6. Regarding the cost of STB, it has been stated that the cost of STB could go up to Rs.3000 for an MPEG4 model. Also, if other costs like installation, activation, maintenance etc. are added it could go up to Rs.4000.
7. On the issue of lifespan of STBs, it has been stated that the manufacturers of STBs or components thereof, give warranty only up to 12 to 18 months and so the operators should be allowed to charge repair charges beyond that period. Another comment is that as per Companies Act, the assets, having value less than Rs.5000, shall be depreciated annually @100% and therefore, the lifespan of STB should not be considered more than 1 year.
8. Regarding security deposit, the apprehensions of MSOs are – (i) the security amount of Rs.400/Rs.800 is too low, (ii) Customer may not return the STB when he moves out. They have also mentioned that insurance companies are not willing to cover such products or services. It has been suggested that the security should be at least Rs.1500 and the security deposit is to be refunded after deducting depreciation @2.5% in addition to rental etc.
9. Consumers have supported the provisions of the draft tariff order and stated that the practices being adopted by the MSOs, at present, are detrimental to the subscribers. All maintenance/replacement/upgradation should be done by the service provider, without any charge to the consumer. This will take care of the portability issue as well, as consumer will know the cost of changing service provider.

#### **Analysis of Comments**

##### *Jurisdiction*

10. The quality of service regulations for DTH and DAS as well as tariff order applicable for all the addressable systems, clearly provides that the service providers providing broadcasting and cable TV services using an addressable system are required to give option to the subscribers for procuring the consumer premises equipment/STB on outright purchase basis or hire purchase basis or rental basis as per the scheme, if any, made by the Authority in this regard. Moreover, due to variegated technologies deployed by different operators, a consumer desiring services of a particular operator generally needs to get the STB from that operator and so, the STB forms an integral part of the services provided by the operator. The Authority is of the view that the standard tariff package prescribed for STB is part and parcel of tariff dispensation. Therefore, in accordance with the provisions already made in the regulations and tariff order, the Authority has come up with this standard tariff package for the STBs which is to be mandatorily offered by all the MSOs to their subscribers.

*Need for prescribing the standard tariff package*

11. An STB is necessarily required at the consumer end for receiving the services offered by a service provider offering broadcasting and cable TV services using addressable system. However, different service providers are deploying different technologies and as a result, the STBs deployed by one operator may not be practically compatible with the network of another operator, hampering easy migration of the subscriber from one operator to another, in case the subscriber wishes to do so, without re-investing in a new STB.
12. The Authority is of the view that the interests of the consumers in this regard can be largely protected through the provision for commercial interoperability of STB. Commercial interoperability provides an exit option for a subscriber in case the subscriber wishes to change the operator/platform for any reason. Accordingly, in the relevant Regulations/ Tariff orders of TRAI, it was mandated that the operators of Digital Addressable Systems shall give an option to every subscriber to procure the STB either on outright purchase basis or hire purchase basis or rental basis, or in accordance with the scheme, if any, prescribed by the Authority.
13. As mentioned above, in case of DTH services, the schemes for Customer Premises Equipments (CPEs) offered to the subscribers by the DTH operators, have wide variations and at times are such that no viable exit option is available to the subscribers. Instead the consumer has to re-invest in new hardware in case of migration from a particular operator or platform. It is not unlikely that the same experience is replicated in the upcoming DAS.
14. In view of the above, to provide an easy exit option to the subscribers, ensure availability of STBs at reasonable price and terms and conditions and, at the same time, to protect the interest of the service providers, this tariff order, prescribing standard tariff package for offering of STB on rental basis, is being prescribed.
15. In addition to the standard tariff packages prescribed by the Authority, operators are free to offer their own schemes for supply of STB to its subscribers in accordance with their business plan and within the existing Regulations/ Tariff Orders. Subscribers shall have option to choose from the standard tariff package prescribed by the Authority and the alternative schemes offered by the operators. The prescribed standard tariff package enables the subscriber to procure the STB with clear, easy to understand, terms and conditions and meets the requirement of consumers as well as the service providers. Therefore, the Authority is of the view that prescribing the standard tariff package would benefit the sector as a whole and would provide effective commercial interoperability.
16. Authority has observed that the operators are offering to its subscribers various types of STBs having different features/ capabilities such as “recording facility”, “Internet/broadband compatibility”, “ High definition/ 3D reception capability” etc., in addition to the basic functionalities. Since for such STBs there would be wide variations in terms of features and cost and hence the Standard Tariff Package is provided only for the basic/ vanilla STBs meant for reception of Standard Definition TV signals (SDTV) conforming to the relevant Indian Standard, if any, set by the Bureau of Indian Standards.
17. The Authority is of the view that prescription of a standard tariff package would promote healthy competition amongst the operators to provide better viewing experience to the consumers at an affordable price so as to retain the existing consumers as well as to rope in new ones. Such competition would ultimately benefit all the stakeholders of the sector, including the consumers.

*Cost of STB considered for prescribing the standard tariff package*

18. In the comments received in response to the consultation paper, the cost of the STB suggested ranges from Rs.3000 to Rs.4000, including the installation and activation charges. In response to a query from TRAI, prior to formulation of the draft tariff order, three major MSOs had informed the cost of the STB to be ranging from Rs.1635 to Rs.1939. This cost included the costs of the STB, CAS, smart card, middleware, and the custom duty and the charges for royalty transportation, freight and insurance. The cost of electronic items, in general, and STB in particular, is consistently falling with time. In view of the above, the cost of STB has been taken as Rs 1750 for formulating the Standard Tariff Package.

*Lifespan of STB*

19. The stakeholders in their comments have stated that that the manufacturer of STBs or components thereof, give warranty only upto 12 to 18 months. The Authority has taken note of this and also the fact that with passage of times the technology and therefore the robustness of electronic devices has improved considerably. However, at the same time, the technology is changing at a fast pace and continuously there is improvement in terms of performance and features of the electronic items and with introduction of better electronic products the older ones tend to become obsolete. The same holds good for the STBs also . Therefore, taking these factors into account the lifespan of the STBs has been taken as three years.

*Returning of STBs*

20. A STB in an addressable system can only be used by a subscriber if it has been duly authorised by its service provider for use in its network. It is unlikely that a subscriber would withhold the STB without any utility for him. More so, when it is linked to the refund of the security deposit in the event of migration to other operator/platform or quitting from the subscription of that operator's services. In view of this the apprehensions of the operators with respect to the non-returning of STBs are not tenable.

*Parameters used to formulate the standard tariff package*

21. The Standard Tariff Package has been worked out on the basis of the following parameters:-

- i. The total cost of STB has been taken as Rs. 1750
- ii. Life span of STB has been taken as 3 years.
- iii. The residual value has been taken as nil.
- iv. Rental per month is based on cost of STB on Equated Monthly Instalment (EMI) Basis @15% per annum (@1.25% per month) for a period of 36 months.
- v. In options where the security deposit is to be refunded, the interest on security deposit has been adjusted in the rental.
- vi. In options where the security deposit is to be adjusted the interest per month on balance security deposit has been adjusted in the rental.